

कथा कॄत

जुलाई-सितम्बर, 2026

मूल्य - ₹ 60

कथा साहित्य
कला एवं
संस्कृति की
त्रैमासिकी

ISSN-2231-2161

वर्ष : 28 अंक : 109

जुलाई-सितम्बर 2026

कथा ग्रंथ

कथासाहित्य, कला एवं संस्कृति की त्रैमासिकी

कहानियां

- 12 गोविन्द मिश्र : काम.... मुझे भी
15 संजय मनहरण सिंह : ख्वाहिशों की धार से मारे जाने को
24 प्रताप दीक्षित : वर्जना की राख में उगा गाछ
28 सत्या शर्मा 'कीर्ति' : छुपमछुपाई
49 विक्रम सिंह : चौकीदार की रूह
60 संतोषी देवी : आधा-अधूरा
63 ऋषि गजपाल : सदाफूल
69 पूजा गुप्ता : संगम घाट पर

लघुकथाएं

- 23 जयप्रकाश मानस : खोया हुआ देवता, स्मृति का गणित (27),
सभा और तालियां (33), फंसा हुआ रास्ता
(62), कहानी का धागा (68)

- 74 महेश शर्मा : आरक्षण शेर की सवारी
80 कृति जैन : आखिरी पेड़ का इन्टरव्यू
89 शोफालिका सिन्हा : डिफॉल्ट

स्मृति शेष : आशा भोसले

- 05 सुजाता राजी : जिदंगी है, बहने दो!

संवाद

- 08 शीला रोहेकर : यहूदी गाथा : यू आर एन आउटसाइडर
द्वारा - डॉ. अर्वातिका सिंह

लेख

- 34 साधना अग्रवाल : हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि
41 डॉ. राजेश कुमार : इतिहास तिमिरनाशक भीमा कोरे गांव : इतिहास
से उपन्यासों तक

कविताएं

- 75 सौरभ कश्यप : चरैवेति, रूपान्तरण, मैं तुझे जीना चाहता हूं, जयघोष
76 देवेश पथ सारिया : चुप्पी के कोड़े की मार खाते हुए, माफीनामा

- 77 सत्य प्रकाश ध्रुव : वे दीवार नहीं रास्ते हैं, हथेलियों पर ठहरी धूप
78 नितेश व्यास : व्यथित वेदना, ओ पखेरू
79 अनामिका यादव : चुप्पियां, अनदेखी अनकही घटनाएं, मैं प्रतीक्षा
में, हृदय का फूटना जरूरी है, अदृश्य कैद

कथा-शोध

- 81 डॉ. प्रीति प्रकाश : पीली छतरी येलो बूट : मेल गेज फीमेल गेज

प्रसंगवश

- 85 पूर्णिमा सहारन : रचनात्मकता का क्षरण और पुरस्कार-संस्कृति
का उभार

राग लंतरानी

- 88 डॉ. मुकेश असीमित : एक पौधे की व्यथा

समीक्षाएं

- 90 राम विनय शर्मा : 'उत्पीड़ितों के विमर्श' से गुजरते हुए (आलोचना/
विमर्श : वीर भारत तलवार)
92 जय प्रकाश मानस : जहां जंगल स्मृति है और आदमी धीरे-धीरे गायब
होता हुआ वर्तमान (उपन्यास : लोकबाबू)
95 संजीव जायसवाल : माटी की गंध और स्मृतियों की सरिता : अलकनंदा
'संजय' सुत (उपन्यास : अर्चना पैन्थली)
97 मनोज कुमार : थाह नारी के सागर मन की (स्त्री केन्द्रित कहानियां
: अशोक गुजराती)
98 प्रगति गुप्ता : युवामन की अनसुलझी व्यथाओं की कथा : मन
के चौहट्टे पर बोनसाई (उपन्यास : सुधा जुगलान)
02 संपादकीय : भविष्य से खिलवाड़
आवरण : बंसीलाल परमार
रेखाचित्र : राजेन्द्र परदेसी

संपादक
शैलेन्द्र सागर

संपादन परामर्श
रजनी गुप्त

सहयोग
मीनू अवस्थी

प्रबन्ध सहायक
राम मूरत यादव

संपादन संचालन : अवैतनिक

संपादकीय सम्पर्क :

डी-107, महानगर विस्तार, लखनऊ-226006

दूरभाष : 09415243310

e-mail : kathakrama@gmail.com

e-mail : kathakrama@rediffmail.com

इस अंक का मूल्य : 60 ₹

सदस्यता शुल्क : व्यक्तिगत त्रैवार्षिक-900 ₹, आजीवन 4000 ₹

संस्थाएं : वार्षिक-400 ₹, त्रैवार्षिक-1100 ₹, आजीवन 5000 ₹

(kathakram, SBI, Mahanagar Branch, Lucknow A/c 10059002392
IFSC-SBIN0008189)

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, प्लॉट नं. 755/99 A, गोयला इन्डस्ट्रियल एरिया, यू.पी.एस.आई.डी.सी.
-देवा रोड, चिनहट, लखनऊ-226019

भविष्य से खिलवाड़

स

ंपादकीय की ये पंक्तियां लिखते समय मन अत्यंत विचलित और आक्रोशित है। देश का युवा सड़कों पर है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अनेक हिस्सों से उनके आंदोलन की खबरें आ रही हैं। इसे कुचलने की हर संभव कोशिश की जा रही है जिसके तहत लाठी चार्ज, अश्रुगैस अमानवीय और हिंस्त्र कार्रवाइयों को पूरी नग्नता और संवेदनहीनता से अमल में लाया जा रहा है। अब तो पैलेट गन और ए.के.47 के उपयोग की भी पुख्ता जानकारी है। सोशल मीडिया व अन्य स्रोतों से आई खबरों, चित्रों व वीडियो को देखकर दिल दहल गया है। सामने खड़े होकर लड़के लाठियों के वार सह रहे हैं और पुलिस को मारने के लिए ललकार रहे हैं। एक एक युवा पर कई लाठियों के वार पड़ रहे हैं। छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और उन्हें पशुओं की तरह घसीटा जा रहा है। कईयों के कपड़े फाड़े जाने की भी खबर है। देख कर असहनीय पीड़ा होती है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी अपनी ही पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमले के हाथों इस जघन्य बर्बरता का शिकार हो रही है। जाहिर है कि ऐसी कार्रवाई सत्ता के वातानुकूलित कक्षों में विराजे मंत्री, संत्री, और उनके जीहुजूर कारिन्दों के अनुमोदन के बिना मुमकिन ही नहीं है। आंदोलन 20 जून 2026 से जारी है और दिनांक 20 जुलाई को, जिस दिन संसद का मानसूत्र सत्र आरम्भ होना था, इन आंदोलनकारियों का संसद की ओर मार्च करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस कार्रवाई को विफल नहीं बल्कि नेस्तनाबूद करने की विस्तृत योजना राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा गहन व गंभीर विचार विमर्श के बाद बनाई गई होगी। ऐसा लगता है कि इसी वजह से दिल्ली के पुलिस कमिशनर का एक दिन पहले तबादला कर दिया गया जैसा अमूमन नहीं किया जाता क्योंकि नए की बनिस्पत पूर्व से तैनात अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर ढंग से डील कर सकता है। दिल्ली पुलिस कमिशनर जैसे अहम पद पर पोस्टिंग अधिकारी की योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर ही की जाती है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पूर्व अधिकारी इस बंदोबस्त को करने में सक्षम नहीं थे। राजनीतिक हाकिमों से मतभेद होने पर ही ऐसा आकस्मिक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके विकास की एक सीख यह भी है कि उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। शब्दों का चयन पूरी सतर्कता के साथ करना चाहिए चाहे संवाद अधिकारियों से हो, राजनीतिज्ञों से अथवा मीडिया से। जरा सी असावधानी से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी मुद्दे/विषय पर दिया वक्तव्य उस शख्स के व्यक्तित्व को परिभाषित करने लगता है, भले ही उसकी मंशा कुछ और हो। कभी कुछ शब्द ताउम्र उसके साथ जुड़ जाते हैं और यदाकदा उद्धृत किए जाते हैं। 15 मई '26 को देश के मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया में सक्रिय बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में 'कॉकरोच' शब्द के प्रयोग से कानून व्यवस्था की कैसी विषम स्थिति खड़ी हो गई है, हमारे सामने है। माननीय न्यायमूर्ति का देश विदेश में जमकर विरोध हुआ है जो स्वाभाविक है। विश्व प्रसिद्ध अमरीका के बॉस्टन विवि में अध्ययनरत अभिजीत दिपके ने एक अराजनीतिक दल 'कॉकरोच जनता पार्टी' का गठन कर लिया और पहले सोशल मीडिया में और फिर कुछ बड़े शहरों में कॉकरोच मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी बीच नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आ गया जिससे उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नीट की पुनर्परीक्षा तक 21 युवाओं की आत्महत्या की अत्यंत दुखद और झकझोरने वाली खबरें आईं। युवाओं द्वारा इसका पूरे देश में जमकर विरोध किया गया और 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था

में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन आरम्भ कर दिए। 6 जून से जन्तर् मन्तर, नई दिल्ली पर धरना आयोजित किया गया जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं की भागीदारी होने लगी। आंदोलन को लद्दाख के लेह निवासी सांसद एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांग्चुक का समर्थन मिला और वह भी 28 जून 2026 को इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। बाद में उनके द्वारा आमरण अनशन आरम्भ कर दिया गया।

20 जुलाई को संसद घेरने का आह्वान उचित निर्णय नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत्ता और लोकतंत्र के प्रतीक संसद तथा जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। स्वाभाविक था कि पुलिस द्वारा इसे रोकने की पुख्ता योजना बनाई गई थी। पुलिस द्वारा तीन दिन पहले सोनम वांग्चुक को वहां से बलपूर्वक हटा कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बहरहाल दूर-दूर से आए युवाओं की भीड़ जन्तर् मन्तर पर जमा हो गई। युवाओं के संसद मार्च को पुलिस द्वारा पूरे दल बल के साथ रोका गया। छात्रों को विरोध करना ही था। हिंसा और तोड़फोड़ होनी ही थी। नतीजतन गंभीर अराजकता की स्थिति खड़ी हो गई। अनेक छात्र छात्राएं पुलिस की हिंसक कार्रवाई का शिकार हुए जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए नाकाफी है। कई पुलिस कर्मियों के घायल होने तथा सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने के भी समाचार आए।

दिव्यत यह है कि छात्रों द्वारा शुरू किए गए अराजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा हाइजेक करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस, आप व अन्य दलों द्वारा इस आंदोलन में रोटी सेंकने की मुहिम शुरू हो गई है और इसे सत्ता और विपक्षियों के टकराव के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों- बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में पिछले दिनों युवाओं द्वारा किए सफल आंदोलन विपक्षी दलों के प्रेरणा स्रोत हैं। अलबत्ता वे जानते हैं कि भारत में यह संभव नहीं है। एक तो भारत अत्यंत विशाल देश है और दूसरे यहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरे तक पैठी हैं। इन पड़ोसी देशों में जिस तरह की हिंसा, मारकाट और तोड़फोड़ द्वारा सत्ता का कायापलट किया गया, वो भारत में अकल्पनीय है।

पर छात्रों के आंदोलन को न तो प्रश्नांकित किया जा सकता है और न ही उसे हल्के में लिया जाना चाहिए। इसका आगाज किसी राजनीतिक कारण या घटना की वजह से नहीं हुआ। पिछले कुछेक सालों में केंद्रीय और राज्य परीक्षाओं में जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, उससे परीक्षा आयोजन व्यवस्था पर युवाओं का भयंकर रोष होना स्वाभाविक है। महीनों की रात दिन की मेहनत के बाद दी गई परीक्षा को रद्द किया जाना छात्रों के

लिए कितना त्रासद और विक्षुब्धकारी होता है, कुछ युवाओं द्वारा की गई आत्महत्याएं इसका दर्दनाक साक्ष्य हैं। आखिर यह युवाओं के भविष्य का सवाल है और उनके साथ एक धिनौना खिलवाड़ भी। सबसे हास्यास्पद यह कि सरकार इसे अपनी विफलता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नतीजतन इसका उत्तरदायित्व तय करने में भी सरकार को संकोच है। वर्तमान शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में नीट परीक्षा के आयोजन की असफलता की यह दूसरी घटना है। पर प्रधान मंत्री द्वारा सख्त कार्रवाई की बात तो कही गई पर ऐसा कुछ नहीं किया गया जो युवाओं को आश्वस्त कर सके और उनका सिस्टम में विश्वास व भरोसा पुख्ता हो। नैतिकता का तकाजा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान खुद त्यागपत्र देते अथवा उन्हें पद से हटाया जाता। साथ ही परीक्षा एजेन्सी एन टी ए के पदाधिकारियों को न सिर्फ हटाया जाता बल्कि उन्हें कठोर दंड देकर जेल में ठूस दिया जाता। ऐसा लगता है कि सरकार को आशंका होगी कि एजेन्सी के अधिकारियों को दंड देने के बाद मंत्री का बचाव करना मुश्किल होगा और इससे सरकार व पार्टी की जबरदस्त किरकिरी होगी।

अपने भविष्य को अंधकारग्रस्त होते देखते युवाओं के आक्रोश, अवसाद व कुंठा के उफान को भला कब तक थामा जा सकता था। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो चुका था और उन्हें इससे बेहतर मुद्दा और मौका भला कहां मिल सकता था।

यह आंदोलन कई मायने में अभूतपूर्व और विशिष्ट है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में यह जेन जी की पहली हुंकार है जो पूरी संजीदगी के साथ इसमें योगदान दे रहे हैं, साथ ही उसे रोचक भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया मजेदार मीम व रील से भरा पड़ा है। तरह तरह के रूप धारण कर वे मनोरंजन कर रहे हैं। बॉलीवाल, क्रिकेट, शतरंज, कार्ड खेलते दिखते हैं, गीत गा रहे हैं और वाटर कैनन की तेज बौछारों के सामने यो यो हनी सिंह का 'आज तू है पानी पानी....' गाकर नाच रहे हैं। कुछ पुलिस से पूछ रहे हैं- अंकल, आज टियर गैस नहीं लाए...?' जाहिर है कि यह आंदोलनरत युवाओं के तनाव को कम करने में सहायक होगा।

केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा अनेक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इधर कुछेक सालों से पेपर लीक होने के समाचार मिल रहे हैं। ज्यादातर परीक्षाएं बेदाग रही हैं। प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा, जेईई के साथ तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनपर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे। जाहिर है कि यदि किसी परीक्षा में पेपरलीक की पुख्ता खबर आती है तो उसके पीछे कोई साजिश, भ्रष्टाचार, लापरवाही ही वजह होगी। तकनीक के इस दौर में परीक्षा एजेंसियों को जबरदस्त सावधानी तथा उच्च तकनीक का प्रयोग करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाएं बिना किसी अवरोध/ आरोप

और सीक्रेसी या सावधानी से समझौता किए बिना सुचारू रूप सम्पन्न हों। रद की गई परीक्षाओं के पुनः सकुशल होने से यह निष्कर्ष निकलना स्वाभाविक है कि पूर्व में कहीं गंभीर चूक या भ्रष्टाचार किया गया है।

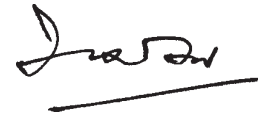
एक पुलिस अधिकारी के तौर पर ऐसे उग्र आंदोलनों का सामना और बंदोबस्त करने के कई अवसर मुझे मिले हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इससे उग्र और व्यापक आंदोलन नहीं हुए हैं। पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक, जातिगत, क्षेत्रीय आदि मुद्दों को लेकर उपद्रवों से दो चार होना पड़ता है। कभी बेहद गंभीर स्थितियां को भी डील करना पड़ा है। मेरठ के सांप्रदायिक दंगे, 1984 का सिख विरोधी आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन में अनेक विषम परिस्थितियों से मेरा सामना हुआ है। कई बार छात्र भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित रहे हैं। इन सभी आंदोलनों में पुलिस को कुछ भिन्न नजरिया रखना पड़ता है और उसी के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आंदोलन का क्या रूप है, कौन और कैसे लोग/समूह उसमें शामिल हैं, कैसी हिंसा और लूटपाट संभावित है, को ध्यान में रखकर ही उनसे निबटने की योजना बनाई जाती है। छात्रों के आंदोलन में पुलिस कर्मियों को यह अहसास बना रहता है कि ये उनके अपने बच्चे हैं। उनके प्रति सहानुभूति और सहृदयता रहती है। अनेक पुलिस अधिकारियों के छात्र नेताओं से अच्छे संबंध भी होते हैं। एक्शन कम उसका भय अधिक बनाया जाता है जो अक्सर कारगर साबित होता है। आखिर ये युवा ही देश का भविष्य हैं।

जंतर मंतर पर आंदोलन लंबे अरसे से चल रहा था पर लगता है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों से संपर्क व

संवाद बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। शायद स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया। संसद घेरने के आह्वान पर पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था और प्रोएक्टिव एप्रोच द्वारा इसे विफल या वापस कराने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए थी।

ऐसे किसी आंदोलन में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ होना अस्वाभाविक नहीं है। वे उस मुहिम के चरित्र, स्वरूप, लक्ष्य व उद्देश्यों को नष्ट, भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे तत्वों पर पुलिस की निगरानी/सतर्कता बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं विध्वंस से निजात दिला सकती है। साथ ही आंदोलन की गरिमा भी बनी रहती है। अहिंसात्मक प्रतिरोध सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है पर असामाजिक तत्व हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को हिंसा, तोड़फोड़ व अराजकता में बदल देते हैं जिससे आंदोलन की शुचिता, नीति व नीयत पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

पुनश्च:- अभी मिले समाचार से पता चला है कि शिक्षा मंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और नीट परीक्षा में हुई धांधली की जिम्मेवारी स्वीकार की है। यह देश के युवाओं और लोकतंत्र की उल्लेखनीय विजय है। हाल के अनेक सालों में आंदोलन स्वरूप किसी केन्द्रीय मंत्री के इस्तीफे का दृष्टांत मेरी स्मृति में नहीं है। युवाओं को बधाई और बधाई..., साथ ही सलाह भी कि इस अद्वितीय उपलब्धि को जश्न व मस्ती में न खो जाने दें। अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इसे पहले कदम के रूप में लें।



अगला अंक (110) : अक्टूबर-दिसम्बर -2026

कथल कथ

मधुरेश, विनोद शाही, दीपक शर्मा, वंदना शुक्ला, डॉ. उमा मीणा, डॉ. उर्वशी, देवेन्द्र पाठक, महारूम, सर्वेश सिंह, अशोक प्रजापति, हैज वरनर वेसलर, डॉ. राहुल कुमार यादव, डॉ. राणा प्रताप, मनोज कुमार, प्रगति गुप्ता, महेश शंकर सिंह, ऋतु त्यागी, जोसे डिसूजा सारामागो, जयप्रकाश मानस, महेश शंकर सिंह आदि।

चुनिन्दा कहानियां, लेख, संवाद, लघु कथाएं, समीक्षा, रपट एवं कला-संस्कृति-रंगमंच से जुड़ी सामग्री। पठनीय तथा संग्रहणीय।

जिंदगी है, बहने दो!

□ सुजाता राजी



आशा भोसले

(08.09.1933–12.04.2026)

अपने को हिन्दी बॉलीवुड का अंतिम मुगल कहने वाली आशा भोसले का जीवन किसी

स्त्री-विमर्श से कम नहीं था। जीवन के तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्होंने जीवन को भरपूर जिया और अपनी शर्तों पर जिया फिर चाहे वो प्रेम हो या संगीत। आशा भोसले ने अपने जीवन के संघर्षों से शिकवा नहीं किया बल्कि उसे चुनौती दी कि 'प्यासी हूं मैं प्यासी रहने दो'। सन् 1930 के दशक में जब भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब हीरो या हीरोइन बनने के लिए अच्छा गायक होना जरूरी था। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग के इतिहास में आजादी से पहले नूरजहां और के. एल सहगल ने प्लेबैक सिंगिंग को अपनी गायकी से लोकप्रियता का एक मुकाम दिया था। गौर करने के बात है कि हिन्दी फिल्म के दर्शकों के लिए फिल्म के पात्रों का गाना गाना पहला अनुभव था। बोलने की ही तरह ही पात्रों का गाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था।

पार्श्व गायन के क्षेत्र में 1940 के दशक में मदनमोहन, अनिल बिस्वास, हेमंत मुखर्जी और गुलाम हैदर जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार और नूरजहां, मुकेश, मोहम्मद रफी, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी गायकों ने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन हिन्दी फिल्मों के इतिहास में सन् 1949 से लेकर लगभग सन् 2000 तक का समय लता-आशा के दौर के रूप में याद किया जाएगा। लगभग 50 सालों का यह समय विशुद्ध पार्श्व-गायन (प्लेबैक सिंगिंग) का स्वर्ण-काल है क्योंकि इस समय में प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में आवाज, संगीत, रिकॉर्डिंग, गायकों

को रॉयल्टी और गायक की पहचान को महत्व दिए जाने को लेकर पाश्चात्य धुने, सुर और साज के इस्तेमाल जैसी कई ऐतिहासिक घटनाएं घटीं। साथ ही बॉलीवुड में मंगेशकर बहनों के एकछत्र-राज से यह धारणा भी टूटी कि अच्छे घर की लड़कियां सार्वजनिक रूप से गाना नहीं गाती हैं। सन् 1949 में लता जी का गाया फिल्म 'महल' का गीत 'आएगा आने वाला' उनका पहला हिट गाना था और इसके साथ ही इस दौर में उनकी पतली, मधुर आवाज ने दर्शकों को अपनी मिठास से सराबोर कर दिया और गायक की पूर्व स्थापित, पारंपरिक भारी आवाज गुजरे जमाने का चलन बन गया। उसी दौर में आगे 'आशा' नाम की आवाज ने भी दस्तक दी लेकिन वे एक चंचल-चपल नदी की तरह थी जो अपने आवेग से सीमाओं का अतिक्रमण करके अपने लिए नया रास्ता बनाने पर आमादा थी।

किसी भी साहित्यकार या कलाकार के योगदान को उसके युग की कसौटी में रख कर ही संपूर्णता में आंका जा सकता है। एक बेहद संस्कारी और परंपरावादी मराठी परिवार में जन्मी आशा भोसले में बचपन से ही बंधी हुई लीक से बाहर जाकर नया आजमाने की ललक थी। राहुल देव वर्मन के गैर पारंपरिक वाद्य यंत्रों (ग्लास, चाकू, लकड़ी, गाड़ी का बोनट, कंघी) और विदेशी संगीत के आलाप को गाने का जोखिम उस समय का कोई भी प्रतिष्ठित गायक नहीं लेना चाहता था। लेकिन आशा ने हिम्मत दिखाई। कहते हैं 1966 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तीसरी